



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

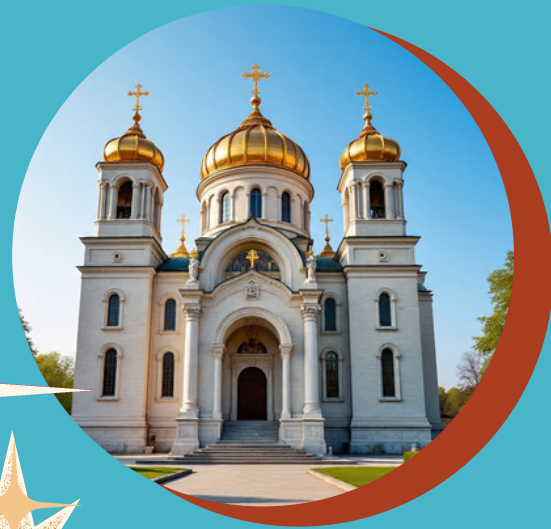


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

8 - 14 FEB 2026

2ND WEEK OF FEBRUARY

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: Which global investment firm received RBI approval to acquire up to 9.99% stake in Federal Bank?

किस वैश्विक निवेश कंपनी को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?

- A) Brookfield / ब्रुकफील्ड
- B) KKR / केकेआर
- C) Blackstone / ब्लैकस्टोन
- D) Carlyle / कार्लाइल
- E) Warburg Pincus / वारबर्ग पिंगस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved Blackstone's acquisition of up to 9.99% stake in Federal Bank.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है।
 - With this approval, Blackstone will become the largest shareholder of Federal Bank.
 - इस मंजूरी के बाद ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा।
 - The total investment value of the deal is approximately ₹6,196 crore.
 - इस सौदे का कुल निवेश मूल्य लगभग ₹6,196 करोड़ है।
 - The acquisition has been approved under RBI norms governing Foreign Portfolio Investors (FPIs) in private sector banks.
 - यह अधिग्रहण निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से संबंधित RBI के नियमों के तहत स्वीकृत किया गया है।
 - The deal highlights the growing interest of foreign investors in India's private banking sector.
 - यह सौदा भारत के निजी बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
-

Ques: Which Regional Rural Bank (RRB) became the first in India to launch a co-branded RuPay credit card?

भारत में सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) कौन सा है?

- A) Assam Gramin Vikash Bank / असम ग्रामीण विकास बैंक
- B) Kerala Gramin Bank / केरल ग्रामीण बैंक
- C) Karnataka Gramin Bank / कर्नाटक ग्रामीण बैंक
- D) Bihar Gramin Bank / बिहार ग्रामीण बैंक
- E) Tripura Gramin Bank / त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या :

- Tripura Gramin Bank (TGB), in collaboration with its sponsor bank Punjab National Bank (PNB), launched a co-branded RuPay credit card.
 - त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (TGB) ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सहयोग से सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
 - With this initiative, TGB became the first Regional Rural Bank (RRB) in India to introduce a co-branded RuPay credit card.
 - इस पहल के साथ TGB भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) बन गया जिसने सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड पेश किया।
 - It is also the first among the eight RRBs sponsored by PNB to achieve this milestone.
 - यह PNB द्वारा प्रायोजित आठ RRBs में भी ऐसा करने वाला पहला बैंक है।
 - The launch was held at Agartala, Tripura, marking the Golden Jubilee (50 years) of Tripura Gramin Bank.
 - यह लॉन्च त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) का प्रतीक है।
-

Ques: What decision did the RBI's Monetary Policy Committee (MPC) take regarding the repo rate in its latest policy review?

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नवीनतम नीति समीक्षा में रेपो रेट पर क्या निर्णय लिया?

- A) Reduced to 5.00% / 5.00% कर दिया
- B) Increased to 5.50% / 5.50% कर दिया
- C) Kept unchanged at 5.25% / 5.25% पर स्थिर रखा
- D) Reduced to 4.75% / 4.75% कर दिया
- E) Increased to 6.00% / 6.00% कर दिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) unanimously decided to keep the repo rate unchanged at 5.25%, continuing the pause on interest rates.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया और ब्याज दरों पर विराम जारी रखा।
- The decision was taken by the Monetary Policy Committee (MPC) amid improving economic growth prospects.
- यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा बेहतर होते आर्थिक परिदृश्य के बीच लिया गया।
- The MPC revised India's GDP growth projection for FY2025–26 to 7.4%, up from the earlier estimate of 7.3%.
- MPC ने FY2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- The policy stance reflects confidence in India's economic momentum following a strong policy and reform-driven week.
- यह नीतिगत रुख मजबूत आर्थिक गति और हालिया नीतिगत फैसलों पर RBI के भरोसे को दर्शाता है।
- Stable inflation conditions and robust growth outlook supported the decision

to maintain the status quo on rates.

- नियंत्रित महंगाई और मजबूत विकास अनुमान के कारण ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

Ques : Under the new Risk-Based Premium (RBP) framework, which category of banks will pay the lowest deposit insurance premium?

नए जोखिम-आधारित प्रीमियम (RBP) ढांचे के तहत कौन-सी श्रेणी के बैंक सबसे कम जमा बीमा प्रीमियम देंगे?

- A) Category A / श्रेणी A
- B) Category B / श्रेणी B
- C) Category C / श्रेणी C
- D) Category D / श्रेणी D
- E) All will pay the same / सभी समान भुगतान करेंगे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या

- From 1 April 2026, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), a subsidiary of RBI, will implement a Risk-Based Premium (RBP) framework.
- 1 अप्रैल 2026 से, RBI की सहायक संस्था DICGC जोखिम-आधारित प्रीमियम (RBP) ढांचा लागू करेगी।
- Under this system, banks will pay 8–12 paise per ₹100 deposit per year, depending on their risk category.
- इस प्रणाली के तहत बैंक ₹100 जमा पर 8 से 12 पैसे प्रति वर्ष प्रीमियम देंगे।
- Category-wise Premium Structure | श्रेणी-वार प्रीमियम संरचना:
 - Category A (Lowest Risk): 8 paise
 - Category B: 10 paise
 - Category C: 11 paise
 - Category D (Highest Risk): 12 paise

- Currently, DICGC charges a flat premium of 12 paise per ₹100 deposit to all banks.
- वर्तमान में DICGC सभी बैंकों से ₹100 जमा पर 12 पैसे का समान प्रीमियम वसूलता है।
- The DICGC Act, 1961 allows differential premium rates for banks based on risk.
- DICGC अधिनियम, 1961 जोखिम के आधार पर अलग-अलग प्रीमियम दरों की अनुमति देता है।
- Banks will be classified into A, B, C and D categories based on DICGC's internal risk assessment.
- बैंकों को DICGC की आंतरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर A, B, C और D श्रेणियों में रखा जाएगा।

Ques: Which organisation approved USD 830 million for India's PM-SETU programme?

भारत के PM-SETU कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस संगठन ने स्वीकृत किए हैं?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- D) New Development Bank (NDB) / नया विकास बैंक
- E) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या :

- The World Bank approved USD 830 million for India's Pradhan Mantri – Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) programme.

- विश्व बैंक ने भारत के PM-SETU (उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार परिवर्तन) कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए।
- The funding aims to upgrade Industrial Training Institutes (ITIs) and improve skilling and employability outcomes across India.
- इस वित्तपोषण का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन कर कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
- The loan is part of the World Bank Group's Country Partnership Framework (CPF) for India (FY 2026–31).
- यह ऋण भारत के लिए विश्व बैंक समूह की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (वित्त वर्ष 2026–31) का हिस्सा है।
- Under the CPF, the World Bank Group envisages USD 8–10 billion in annual financing for India.
- इस फ्रेमवर्क के तहत भारत को प्रति वर्ष 8–10 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है।
- The loan has a tenure of 19.5 years, including a 4-year grace period.
- इस ऋण की अवधि 19.5 वर्ष है, जिसमें 4 वर्ष की मोहलत अवधि (Grace Period) शामिल है।

Ques: What disinvestment and asset monetisation target has the Centre set for FY27 under the Union Budget 2026?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 के तहत FY27 के लिए विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

- A) ₹34,000 crore
- B) ₹47,000 crore
- C) ₹60,000 crore
- D) ₹75,000 crore
- E) ₹80,000 crore

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या :

- The Centre has set an ambitious target of ₹80,000 crore from disinvestment and asset monetisation for FY27, indicating a renewed push to strengthen non-tax revenues under Union Budget 2026.
- केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 के तहत FY27 के लिए विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से ₹80,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे गैर-कर राजस्व को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- The ₹80,000 crore target has been budgeted under Miscellaneous Capital Receipts for 2026–27.
- ₹80,000 करोड़ का लक्ष्य 2026–27 के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियों (Miscellaneous Capital Receipts) के अंतर्गत रखा गया है।
- This marks a sharp increase from the revised estimate of about ₹34,000 crore for the current financial year.
- यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान ₹34,000 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है।
- For FY26, the government had originally budgeted ₹47,000 crore, but weak execution led to a downward revision.
- FY26 में सरकार ने शुरू में ₹47,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन कमजोर कार्यान्वयन के कारण इसमें कटौती करनी पड़ी।
- Actual receipts in FY25 stood at just ₹20,214 crore, highlighting persistent challenges in achieving disinvestment targets.
- FY25 में वास्तविक प्राप्तियां केवल ₹20,214 करोड़ रहीं, जो विनिवेश लक्ष्यों को हासिल करने में लगातार आ रही चुनौतियों को दर्शाता है।

Ques: RBI has increased the collateral-free loan limit for Micro and Small Enterprises (MSEs) to how much?

RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा कितनी कर दी है?

- A) ₹10 lakh
- B) ₹15 lakh
- C) ₹20 lakh
- D) ₹25 lakh
- E) ₹50 lakh

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has doubled the collateral-free loan limit for Micro and Small Enterprises (MSEs) from ₹10 lakh to ₹20 lakh.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी है।
 - The enhanced limit will apply to all loans sanctioned or renewed on or after April 1.
 - बढ़ी हुई ऋण सीमा 1 अप्रैल या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।
 - The move aims to improve access to credit for MSEs and support their growth.
 - इस कदम का उद्देश्य MSEs को आसान ऋण उपलब्ध कराना और उनके विकास को समर्थन देना है।
 - Collateral-free loans reduce dependence on asset-backed lending, especially for small businesses.
 - बिना गारंटी ऋण छोटे व्यवसायों की संपत्ति-आधारित ऋण पर निर्भरता को कम करते हैं।
 - The decision is part of RBI's broader strategy to strengthen MSME financing in India.
 - यह निर्णय भारत में MSME वित्तपोषण को मजबूत करने की RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
-
-

Ques: The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has revised the base year of the Consumer Price Index (CPI) to which year, introducing major changes in item weights and coverage?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष बदलकर किस वर्ष का किया है, जिसमें वस्तुओं के भार और कवरेज

में बड़े बदलाव किए गए हैं?

- A) 2015
- B) 2018
- C) 2020
- D) 2022
- E) 2024

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has revised the CPI base year from 2011–12 to 2024.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने CPI का आधार वर्ष 2011–12 से बदलकर 2024 कर दिया है।
- The revised CPI series is named CPI 2024.
- संशोधित CPI श्रृंखला का नाम CPI 2024 रखा गया है।
- The weight of Food & Beverages has been reduced significantly from 45.86% to 36.75%.
- खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है।
- The weight of Housing has increased sharply from 10.07% to 17.66%, due to improved rent measurement methods, which may push housing inflation upward.
- आवास का भार 10.07% से बढ़ाकर 17.66% कर दिया गया है, बेहतर किराया मापन पद्धति के कारण इससे आवास मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
- The revised CPI basket now includes 358 items, up from 299 earlier.
- संशोधित CPI टोकरी में अब 358 वस्तुएँ शामिल हैं, जो पहले 299 थीं।
- Education has been introduced as a standalone category in the reclassified CPI groups.
- शिक्षा को पुनर्वर्गीकृत CPI श्रेणियों में एक स्वतंत्र समूह के रूप में शामिल किया गया है।
- Price data will be collected from 1,465 rural markets and 1,395 urban markets across 434 towns.
- मूल्य आँकड़े 434 नगरों में 1,465 ग्रामीण बाजारों और 1,395 शहरी बाजारों से एकत्र

किए जाएंगे।

- Additionally, 12 online markets in cities with a population exceeding 2.5 million will be included to capture weekly prices from e-commerce platforms.
- इसके अतिरिक्त, 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 12 ऑनलाइन बाजारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से साप्ताहिक मूल्य एकत्र करने के लिए जोड़ा जाएगा।
- CPI 2024 adopts the COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose) framework to enhance international comparability.
- CPI 2024 अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए COICOP 2018 ढांचे को अपनाता है।

Ques: What is the maximum one-time compensation proposed by RBI for victims of digital fraud?

डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए RBI द्वारा प्रस्तावित अधिकतम एकमुश्त मुआवजा कितना है?

- A) ₹10,000
- B) ₹15,000
- C) ₹20,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a one-time compensation for bank customers affected by digital frauds.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल धोखाधड़ी से प्रभावित बैंक ग्राहकों के लिए एकमुश्त मुआवजे का प्रस्ताव रखा है।
- The maximum compensation amount is ₹25,000 per customer.
- प्रति ग्राहक अधिकतम ₹25,000 तक मुआवजा दिया जाएगा।
- The compensation will be provided from RBI's Depositor Education and

Awareness (DEA) Fund.

- यह मुआवजा RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड से दिया जाएगा।
- The scheme will apply to small-value digital fraudulent transactions only.
- यह योजना केवल कम राशि वाले डिजिटल धोखाधड़ी लेनदेन पर लागू होगी।
- The compensation facility will be provided only once per customer.
- यह सुविधा प्रति ग्राहक केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
- The objective of the scheme is to create awareness so that customers do not fall prey to online frauds again.
- इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे दोबारा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार न हों।
- The announcement was made by RBI Governor Sanjay Malhotra.
- इस योजना की घोषणा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई।

Ques: Which bank launched the “Rooftop Solar Finance” product to support MSMEs in adopting solar energy systems?

MSMEs को सोलर ऊर्जा प्रणाली अपनाने में सहायता के लिए “रूफटॉप सोलर फाइनेंस” उत्पाद किस बैंक ने लॉन्च किया?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank launched “Rooftop Solar Finance”, a dedicated financing product to help Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) adopt solar energy systems on commercial rooftops.
- एक्सिस बैंक ने “रूफटॉप सोलर फाइनेंस” नामक नया वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है,

जिसका उद्देश्य MSMEs को व्यावसायिक छतों पर सोलर ऊर्जा प्रणाली अपनाने में सहायता करना है।

- Under this product, MSMEs can avail loans ranging from ₹10 lakh to ₹2 crore without any collateral requirement.
- इस योजना के तहत MSMEs ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का ऋण बिना किसी जमानत के प्राप्त कर सकते हैं।
- The financing facility is available through Axis Bank's branch network across India.
- यह वित्तीय सुविधा एक्सिस बैंक की देशभर की शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
- The repayment tenure ranges between 4 to 7 years, enabling businesses to align repayments with their cash flows.
- 4 से 7 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि व्यवसायों को कैश फ्लो के अनुसार भुगतान प्रबंधन में मदद करती है।
- The initiative supports clean energy adoption, cost reduction, and sustainability among MSMEs.
- यह पहल स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, लागत में कमी और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को बढ़ावा देती है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: Which institution is planning to issue revised guidelines for the Kisan Credit Card (KCC) scheme?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश कौन-सा संस्थान जारी करने वाला है?

A) Ministry of Agriculture / कृषि मंत्रालय

- B) NABARD / नाबार्ड
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) is set to issue revised guidelines for banks under the Kisan Credit Card (KCC) scheme.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने वाला है।
- The objective is to boost the farm sector by expanding coverage and streamlining KCC operations.
- इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, कवरेज बढ़ाना और संचालन को सरल बनाना है।
- Proposed changes include standardisation of crop seasons and extension of KCC tenure up to six years.
- प्रस्तावित बदलावों में फसल मौसम का मानकीकरण और KCC अवधि को छह वर्ष तक बढ़ाना शामिल है।
- Drawing limits will be aligned with the scale of finance for each crop season.
- ड्रॉइंग लिमिट को प्रत्येक फसल मौसम के वित्त पैमाने से जोड़ा जाएगा।
- Expenses on technological interventions may also be included under KCC.
- तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े खर्च भी KCC के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं।
- RBI Governor Sanjay Malhotra stated that draft guidelines will be issued shortly, following a comprehensive review of the scheme.
- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि योजना की व्यापक समीक्षा के बाद मसौदा दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे।
- As per SBI, collateral is waived up to ₹2 lakh, and up to ₹3 lakh under tie-up arrangements.
- SBI के अनुसार ₹2 लाख तक बिना जमानत, और टाई-अप व्यवस्था में ₹3 लाख तक ऋण उपलब्ध है।

- A 3% interest subvention is available on timely repayment for loans up to ₹3 lakh.
 - समय पर भुगतान पर ₹3 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
-
-

Ques: Which district became the first in India to achieve 100% insurance coverage under the “Insurance for All by 2047” initiative?

“इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047” पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना?

- A) Jaipur (Rajasthan) / जयपुर
- B) Alwar (Rajasthan) / अलवर
- C) Indore (Madhya Pradesh) / इंदौर
- D) Surat (Gujarat) / सूरत
- E) Gurugram (Haryana) / गुरुग्राम

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Alwar district in Rajasthan became the first district in India to achieve 100% insurance coverage under the “Insurance for All by 2047” initiative.
- राजस्थान का अलवर जिला “इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047” पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया।
- The initiative is a joint effort of the Government of India (GoI) and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- यह पहल भारत सरकार (GoI) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की संयुक्त पहल है।
- As part of the drive, 1,367 individuals above the age of 10 years were brought under insurance coverage through door-to-door surveys, ensuring full saturation.
- इस अभियान के तहत घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से 10 वर्ष से अधिक आयु के 1,367

लोगों को बीमा के दायरे में लाया गया, जिससे पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हुआ।

- The insurance policies were issued by United India Insurance Company Limited (UIIC).
- ये बीमा पॉलिसियाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) द्वारा जारी की गईं।
- The achievement supports India's long-term goal of universal insurance coverage by 2047, marking 100 years of Independence.
- यह उपलब्धि 2047 तक सार्वभौमिक बीमा कवरेज के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य (स्वतंत्रता के 100 वर्ष) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Ques: Which NBFCs have been exempted from mandatory RBI registration as per the latest RBI decision?

RBI के हालिया निर्णय के अनुसार किन NBFCs को अनिवार्य RBI पंजीकरण से छूट दी गई है?

- A) All NBFCs operating in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी NBFCs
- B) NBFCs with assets above ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले NBFCs
- C) NBFCs with assets below ₹1,000 crore and no public funds or customer interface / ₹1,000 करोड़ से कम संपत्ति वाले, बिना सार्वजनिक धन और ग्राहक इंटरफेस वाले NBFCs
- D) Only government-owned NBFCs / केवल सरकारी स्वामित्व वाले NBFCs
- E) Foreign NBFCs operating in India / भारत में कार्यरत विदेशी NBFCs

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has exempted certain NBFCs with assets

below ₹1,000 crore from mandatory registration.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ₹1,000 करोड़ से कम संपत्ति वाले कुछ NBFCs को अनिवार्य पंजीकरण से छूट दी है।
- This exemption applies only to NBFCs that do not access public funds and do not have any customer interface.
- यह छूट केवल उन NBFCs पर लागू होगी जिनकी सार्वजनिक धन तक पहुंच नहीं है और जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।
- The move aims to reduce compliance burden on smaller NBFCs while ensuring that systemic financial stability is not compromised.
- इस कदम का उद्देश्य छोटे NBFCs पर अनुपालन बोझ कम करना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
- RBI has also proposed to remove the requirement of prior approval for certain NBFCs to open more than 1,000 branches.
- RBI ने कुछ NBFCs के लिए 1,000 से अधिक शाखाएँ खोलने हेतु पूर्व अनुमोदन की शर्त हटाने का प्रस्ताव भी रखा है।
- RBI will continue to monitor liquidity and credit flow in the economy.
- RBI अर्थव्यवस्था में तरलता और ऋण प्रवाह की निगरानी जारी रखेगा।

Ques: What major change has the Reserve Bank of India (RBI) made under the Voluntary Retention Route (VRR) for Foreign Portfolio Investors (FPIs)?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए वॉलंटरी रिटेंशन रूट (VRR) के तहत कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Increased investment cap to ₹5 lakh crore / निवेश सीमा ₹5 लाख करोड़ तक बढ़ाई
- B) Removed the ₹2.5 lakh crore overall investment limit / ₹2.5 लाख करोड़ की कुल निवेश सीमा हटा दी
- C) Restricted VRR only to equity investments / VRR को केवल इक्विटी निवेश तक सीमित किया
- D) Suspended VRR temporarily / VRR को अस्थायी रूप से निलंबित किया

E) Introduced new tax on FPI debt investments / FPI ऋण निवेश पर नया कर लगाया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has removed the overall investment cap of ₹2.5 lakh crore under the Voluntary Retention Route (VRR) for FPIs.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FPIs के लिए VRR के तहत ₹2.5 लाख करोड़ की कुल निवेश सीमा को हटा दिया है।
 - Under the revised framework, VRR investments will now be governed by the existing investment ceilings under the General Route.
 - संशोधित ढांचे के तहत अब VRR के माध्यम से निवेश सामान्य मार्ग (General Route) की मौजूदा निवेश सीमाओं के अनुसार नियंत्रित होंगे।
 - The move aims to deepen domestic bond markets and improve the stability of capital flows.
 - इस कदम का उद्देश्य घरेलू बॉन्ड बाजार को गहराई देना और पूंजी प्रवाह की स्थिरता को बढ़ाना है।
 - It provides greater flexibility to foreign investors to deploy long-term funds in Indian debt markets.
 - यह विदेशी निवेशकों को भारतीय ऋण बाजार में दीर्घकालिक निवेश के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
 - The decision comes amid tight global financial conditions and rising government borrowing, to boost FPI participation in the bond market.
 - यह निर्णय कड़े वैश्विक वित्तीय हालात और बढ़ती सरकारी उधारी के बीच बॉन्ड बाजार में FPI भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
-

Ques: By what percentage did State Bank of India's (SBI) net profit rise in Q3FY26?

Q3FY26 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा?

- A) 15%
- B) 18.5%
- C) 21%
- D) 24.5%
- E) 30%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) reported a 24.5% year-on-year increase in standalone net profit to ₹21,028 crore in Q3FY26.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने Q3FY26 में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 24.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹21,028 करोड़ का लाभ कमाया।
- Net Interest Income (NII) rose by 9.04%, while Net Interest Margin (NIM) eased slightly to 3.12% from 3.15% a year ago.
- नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 9.04% की वृद्धि हुई, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) मामूली घटकर 3.12% रह गया (पिछले वर्ष 3.15%)।
- Gross advances increased by 15.17% to ₹46.8 lakh crore, and gross deposits rose by 9.02% to ₹57 lakh crore.
- ग्राँस एडवांस 15.17% बढ़कर ₹46.8 लाख करोड़, जबकि ग्राँस डिपॉजिट 9.02% बढ़कर ₹57 लाख करोड़ हो गया।
- Asset quality improved, with Gross NPAs declining 12.3% to ₹73,637 crore and Net NPAs falling 15.74% to ₹18,012 crore.
- एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, जहाँ ग्राँस NPA 12.3% घटकर ₹73,637 करोड़ और नेट NPA 15.74% घटकर ₹18,012 करोड़ रह गया।
- The domestic Credit–Deposit ratio stood at 72.98%, improving by 404 basis points YoY.
- घरेलू क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 72.98% रहा, जो साल-दर-साल 404 बेसिस पॉइंट का सुधार दर्शाता है।
- SBI stated it has adequate capital and liquidity buffers to support future credit growth.
- SBI ने कहा कि भविष्य की क्रेडिट वृद्धि को समर्थन देने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है।

Ques: How much gold did the Reserve Bank of India (RBI) purchase in 2025, and what was the main reason for the sharp decline compared to 2024?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में कितना सोना खरीदा और 2024 की तुलना में इसमें भारी गिरावट का मुख्य कारण क्या था?

- A) 16 tonnes; weak global demand / 16 टन; वैश्विक मांग में कमी
- B) 25 tonnes; low foreign reserves / 25 टन; कम विदेशी मुद्रा भंडार
- C) 73 tonnes; stable gold prices / 73 टन; स्थिर सोने की कीमतें
- D) 40 tonnes; change in RBI policy / 40 टन; आरबीआई नीति में बदलाव
- E) 4 tonnes; very high gold prices / 4 टन; सोने की बहुत अधिक कीमतें

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) purchased only 4 tonnes of gold in 2025, a sharp decline from 73 tonnes in 2024.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में केवल 4 टन सोना खरीदा, जो 2024 के 73 टन की तुलना में काफी कम है।
- The primary reason for the slowdown was very high gold prices.
- इस गिरावट का मुख्य कारण सोने की अत्यधिक ऊँची कीमतें रहीं।
- RBI's quarter-wise gold purchases in 2025 were: 3.4 tonnes (Q1), 0.4 tonnes (Q2), 0.2 tonnes (Q3), and 0 tonnes (Q4).
- 2025 में आरबीआई की तिमाही सोना खरीद इस प्रकार रही: Q1–3.4 टन, Q2–0.4 टन, Q3–0.2 टन, Q4–0 टन।
- In comparison, RBI bought 16 tonnes in 2023 and 77 tonnes in 2021, making 2025 one of the lowest gold purchase years.
- तुलना में, आरबीआई ने 2023 में 16 टन और 2021 में 77 टन सोना खरीदा था, जिससे 2025 सबसे कम खरीद वाले वर्षों में शामिल हो गया।
- According to the World Gold Council (WGC), global central banks purchased

328 tonnes of gold in 2025, slightly lower than 345 tonnes in 2024.

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने 2025 में 328 टन सोना खरीदा, जो 2024 के 345 टन से थोड़ा कम है।
- Poland was the largest gold buyer in 2025 with 102 tonnes, followed by Kazakhstan (57 tonnes) and Azerbaijan (53 tonnes).
- पोलैंड 2025 में 102 टन के साथ सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा, इसके बाद कज़ाखस्तान (57 टन) और अज़रबैजान (53 टन) रहे।

Ques: Mission SAKSHAM, launched by the Reserve Bank of India (RBI), is related to capacity building of which sector?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम किस क्षेत्र की क्षमता निर्माण से संबंधित है?

- A) Commercial Banks / वाणिज्यिक बैंक
- B) Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- C) Urban Cooperative Banks / शहरी सहकारी बैंक
- D) NBFCs / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- E) Payment Banks / भुगतान बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Mission SAKSHAM (Sahakari Bank Kshamta Nirman) is an initiative of the Reserve Bank of India (RBI) to strengthen Urban Cooperative Banks (UCBs).
- मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को सशक्त बनाना है।
- The mission focuses on enhancing managerial skills, technical capabilities, and operational resilience of UCBs.
- इस मिशन का उद्देश्य UCBs की प्रबंधकीय क्षमता, तकनीकी दक्षता और परिचालन मजबूती को बढ़ाना है।

- It will function as a sector-wide capacity-building and certification framework.
- यह एक क्षेत्र-व्यापी क्षमता निर्माण एवं प्रमाणन ढांचा होगा।
- Training will be delivered through physical training programmes and a scalable digital learning platform.
- प्रशिक्षण भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा।
- Around 1.4 lakh personnel across various functions in UCBs will be trained under the mission.
- इस मिशन के तहत UCBs के विभिन्न कार्यों से जुड़े लगभग 1.4 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- RBI highlighted that UCBs play a key role in financial inclusion and serving the unbanked population.
- RBI ने बताया कि UCBs वित्तीय समावेशन और बैंकिंग से वंचित वर्गों की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Ques: What is the theme of Financial Literacy Week (FLW) 2026 observed by the Reserve Bank of India (RBI)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मनाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) 2026 की थीम क्या है?

- A) Digital Banking for All / सभी के लिए डिजिटल बैंकिंग
- B) Safe Payments, Secure Nation / सुरक्षित भुगतान, सुरक्षित राष्ट्र
- C) KYC – Your First Step to Safe Banking / KYC – सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम
- D) Financial Inclusion for Growth / विकास के लिए वित्तीय समावेशन
- E) Cyber Safety Awareness / साइबर सुरक्षा जागरूकता

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) will observe Financial Literacy Week (FLW) 2026 from February 9 to 13, 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 9 से 13 फरवरी 2026 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) 2026 मनाएगा।
- The theme of FLW 2026 is “KYC – Your First Step to Safe Banking”.
- FLW 2026 की थीम है — “KYC – सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम”।
- The initiative aims to educate customers about periodic KYC updates, digital safety, and fraud prevention.
- इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को नियमित KYC अपडेट, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करना है।
- RBI has been conducting Financial Literacy Week every year since 2016.
- RBI वर्ष 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है।
- KYC updation is required periodically based on customer risk category or immediately when personal details change (address, mobile number, name, signature, etc.).
- KYC अपडेट ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार समय-समय पर या व्यक्तिगत विवरण में बदलाव होने पर तुरंत आवश्यक होता है।
- As per RBI norms, re-KYC is mandatory every 2 years for high-risk customers, 8 years for medium-risk customers, and 10 years for low-risk customers, or earlier if required by the bank.
- RBI के अनुसार हाई-रिस्क ग्राहकों के लिए 2 वर्ष, मीडियम-रिस्क के लिए 8 वर्ष और लो-रिस्क ग्राहकों के लिए 10 वर्ष में re-KYC अनिवार्य है, या बैंक के कहने पर पहले भी।

Ques: What are the key recommendations of the 16th Finance Commission for the period 2026–31?

16वें वित्त आयोग (2026–31) की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- A) Reduced states’ share to 40% and relaxed fiscal deficit norms
- B) Increased states’ share to 45% with higher unconditional cash transfers
- C) Retained states’ share at 41% with focus on fiscal discipline and outcome-based spending
- D) Abolished horizontal devolution and replaced it with fixed grants
- E) Removed deficit limits for states to boost welfare spending

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The 16th Finance Commission (FC) has recommended retaining the States' share in the divisible pool of central taxes at 41%, the same as recommended by the 15th Finance Commission.
- 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, जो 15वें वित्त आयोग के समान है।

Tax Devolution | कर हस्तांतरण

- Vertical Devolution: 41% of the Central Government's divisible tax pool will be transferred to States.
- वर्टिकल डिवोल्यूशन: केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों को दिया जाएगा।
- Horizontal Devolution: A formula-based mechanism will decide the inter-se share of each State from this 41% pool.
- हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन: 41% राशि में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा सूत्र-आधारित व्यवस्था से तय होगा।

Grants Recommendation | अनुदान सिफारिशें

- The 16th FC recommended total grants worth ₹9.47 lakh crore for the five-year period (2026–31).
- 16वें वित्त आयोग ने ₹9.47 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।
- **Grants to Local Bodies:**
 - Total: ₹8 lakh crore
 - ₹4.4 lakh crore for rural local bodies
 - ₹3.6 lakh crore for urban local bodies
- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:
 - कुल: ₹8 लाख करोड़

- ₹4.4 लाख करोड़ ग्रामीण निकायों के लिए
- ₹3.6 लाख करोड़ शहरी निकायों के लिए

- Additional grants are earmarked for disaster management.
- आपदा प्रबंधन के लिए भी अनुदान शामिल हैं।

Fiscal Discipline Emphasis | राजकोषीय अनुशासन पर जोर

- Caps State fiscal deficit at 3% of GSDP.
- राज्यों के वित्तीय घाटे को GSDP के 3% तक सीमित किया गया।
- Calls for ending off-budget borrowings and rationalising subsidies.
- ऑफ-बजट उधारी समाप्त करने और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर बल।
- Strong emphasis on outcome-based expenditure and greater transparency in tax transfer data.
- परिणाम-आधारित खर्च और कर हस्तांतरण डेटा में पारदर्शिता पर विशेष जोर।

All About the Finance Commission | वित्त आयोग से संबंधित तथ्य:

- Constituted by: President of India
- गठन: भारत के राष्ट्रपति द्वारा
- Constitutional Basis: Article 280 of the Indian Constitution
- संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280
- Frequency: Every five years
- अवधि: प्रत्येक पाँच वर्ष में
- Total Members: 5 (1 Chairman + 4 Members)
- कुल सदस्य: 5 (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य)

16th Finance Commission Details | 16वां वित्त आयोग:

- Tenure: 1 April 2026 – 31 March 2031
- कार्यकाल: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031
- Chairman: Dr. Arvind Panagariya
- अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया
- Full-time Members : Annie George Mathew – Retired bureaucrat and Manoj Panda – Economist

- पूर्णकालिक सदस्य : Annie George Mathew – सेवानिवृत्त नौकरशाह, मनोज पांडा – अर्थशास्त्री
 - Part-time Members : Soumya Kanti Ghosh – Chief Economic Advisor, SBI and T. Rabi Sankar – Deputy Governor, RBI
 - अंशकालिक सदस्य : सौम्य कांति घोष – मुख्य आर्थिक सलाहकार, SBI, टी. रबी शंकर – डिप्टी गवर्नर, RBI
 - Secretary: Ritvik Ranjanam Pandey
 - सचिव: ऋत्विक् रंजनम पांडे
-

Ques: What is the main objective of rolling out Unified Payments Interface (UPI) in Malaysia?

मलेशिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To promote cryptocurrency transactions / क्रिप्टोकॉरेन्सी लेनदेन को बढ़ावा देना
- B) To enable seamless cross-border digital payments / निर्बाध सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना
- C) To replace Malaysia's banking system / मलेशिया की बैंकिंग प्रणाली को बदलना
- D) To introduce a new currency in Malaysia / मलेशिया में नई मुद्रा शुरू करना
- E) To establish a joint central bank / संयुक्त केंद्रीय बैंक स्थापित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi announced that UPI will soon be rolled out in Malaysia.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि UPI को जल्द ही मलेशिया में शुरू किया जाएगा।
- The initiative aims to enable seamless cross-border digital payments between India and Malaysia.
- इस पहल का उद्देश्य भारत और मलेशिया के बीच निर्बाध सीमा-पार डिजिटल

भुगतान को सक्षम बनाना है।

- The rollout is expected to boost business, tourism, and remittance flows between the two countries.
- इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और प्रेषण (रेमिटेंस) को बढ़ावा मिलेगा।
- PM Modi stated that India is globally recognised as a “trusted partner for growth,” reflected in recent trade agreements with the UK, US, and EU.
- पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर “विकास के लिए विश्वसनीय भागीदार” के रूप में देखा जाता है, जो यूके, यूएस और ईयू के साथ व्यापार समझौतों में परिलक्षित होता है।
- He described India–Malaysia relations under the guiding principle of “IMPACT” – India-Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation.
- उन्होंने भारत–मलेशिया संबंधों को “IMPACT” – India-Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation के सिद्धांत के तहत बताया।
- PM Modi emphasized deeper regional cooperation by stating, “India’s success is Malaysia’s success, and it is Asia’s success.”
- पीएम मोदी ने कहा, “भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है, और यह एशिया की सफलता है,” जिससे क्षेत्रीय सहयोग की गहराई उजागर होती है।

Ques: Which bank has become India’s first custodian to enable Foreign Portfolio Investor (FPI) registration and account opening through Electronic Signatures?

इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पंजीकरण और खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक कौन सा है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Kotak Mahindra Bank has become India's first custodian to enable FPI registration and account opening through Electronic Signatures.
- कोटक महिंद्रा बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से FPI पंजीकरण और खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक बन गया है।
- The bank completed the entire account-opening and licensing process digitally, without any physical paperwork.
- बैंक ने पूरी खाता खोलने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बिना किसी भौतिक दस्तावेज़ के डिजिटल रूप से पूरा किया।
- This move follows the Securities and Exchange Board of India (SEBI) operationalising a unified digital workflow in January 2026.
- यह पहल सेबी (SEBI) द्वारा जनवरी 2026 में लागू किए गए एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो के बाद की गई है।
- The initiative enhances ease of doing business, reduces processing time, and boosts India's attractiveness for foreign investors.
- यह पहल ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देती है, प्रक्रिया समय को कम करती है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक बनाती है।

About Kotak Mahindra Bank :

- Established : 1986
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Ashok Vaswani
- Tagline : Let's make money simple

**Ques: Which Act enabled the implementation of 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the insurance sector in India from February 5, 2026?
भारत में बीमा क्षेत्र में 5 फरवरी 2026 से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लागू करने वाला अधिनियम कौन-सा है?**

- A) Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 / बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
- B) Insurance Act, 1938 / बीमा अधिनियम, 1938
- C) Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 / सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025
- D) Life Insurance Corporation Act, 1956 / जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
- E) Digital Personal Data Protection Act, 2023 / डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India implemented 100% FDI in the insurance sector on February 5, 2026 through the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, except Section 25, which deals with common officers and whole-time officers.
- भारत सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से 5 फरवरी 2026 से बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई लागू किया, जिसमें धारा 25 को अपवाद रखा गया है।
- The Act amends three major laws: Insurance Act, 1938; LIC Act, 1956; and IRDAI Act, 1999.
- यह अधिनियम बीमा अधिनियम, 1938; एलआईसी अधिनियम, 1956; और IRDAI अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है।
- The Chairman, MD, or CEO of an insurance company must be an Indian citizen, and mergers between insurance and non-insurance companies are allowed.
- बीमा कंपनी के चेयरमैन, एमडी या सीईओ का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है तथा बीमा और गैर-बीमा कंपनियों के विलय की अनुमति दी गई है।
- The FDI cap in insurance has increased gradually:
26% (pre-2015) → 49% (2015) → 74% (2021) → 100% (2026).
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा क्रमशः बढ़ाई गई: 26% → 49% → 74% → 100%।
- India's insurance penetration stands at 3.7% of GDP, which is below the

global average of 7%.

- भारत की बीमा पैठ जीडीपी का 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से कम है।
- Prior regulatory approval for share transfer has been increased from 1% to 5%, and Net Owned Fund for Foreign Reinsurance Branches has been reduced from ₹5,000 crore to ₹1,000 crore.
- शेयर हस्तांतरण के लिए पूर्व नियामक अनुमोदन सीमा 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फंड ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ किया गया है।
- LIC has been granted autonomy to open Zonal Offices and align foreign offices with local laws.
- एलआईसी को जोनल कार्यालय खोलने की स्वायत्तता दी गई है।
- A Policyholders' Education and Protection Fund will be established, policyholder data must comply with DPDP Act, 2023, and IRDAI has been empowered to disgorge wrongful gains.
- पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की स्थापना होगी, डेटा सुरक्षा DPDP अधिनियम, 2023 के अनुरूप होगी और IRDAI को गलत लाभ की वसूली का अधिकार दिया गया है।

Ques: Why were six Regional Rural Banks (RRBs) altered in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में छह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में परिवर्तन क्यों किया गया?

- A) Due to privatization of Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के कारण
- B) Due to implementation of Basel III norms / बेसल-III मानदंडों के कार्यान्वयन के कारण
- C) As part of the Government's "One State, One RRB" consolidation drive / सरकार की "वन स्टेट, वन RRB" समेकन नीति के तहत
- D) Due to merger of RRBs with cooperative banks / आरआरबी के सहकारी बैंकों में विलय के कारण

E) Due to non-compliance with RBI capital norms / आरबीआई पूंजी मानदंडों का पालन न करने के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Six Regional Rural Banks (RRBs) have been altered in the Second Schedule of the RBI Act, 1934 as part of the Government's "One State, One RRB" consolidation drive (Phase-4).

- सरकार की "वन स्टेट, वन आरआरबी" समेकन योजना (चरण-4) के तहत छह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिवर्तन किया गया है।

- This consolidation reduced the total number of RRBs from 43 to 28, effective May 1, 2025.

- इस प्रक्रिया से 1 मई 2025 से आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई।

- As a result of mergers, the names of six RRBs were changed and officially updated in the Second Schedule:

- Assam Gramin Vikash Bank → Assam Gramin Bank

- Chhattisgarh Rajya Gramin Bank → Chhattisgarh Gramin Bank

- Jharkhand Rajya Gramin Bank → Jharkhand Gramin Bank

- Kerala Gramin Bank → Kerala Grameena Bank

- Puduvai Bharathiyar Grama Bank → Puducherry Grama Bank

- Sarva Haryana Gramin Bank → Haryana Gramin Bank

- The Second Schedule of the RBI Act, 1934 lists all Scheduled Banks in India.

- RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में भारत के सभी अनुसूचित बैंक सूचीबद्ध होते हैं।

- Section 2(e) defines a Scheduled Bank, while Section 42(6)(b) empowers RBI to alter or exclude bank names due to mergers or restructuring.

- धारा 2(e) अनुसूचित बैंक को परिभाषित करती है और धारा 42(6)(b) आरबीआई को विलय के कारण नाम बदलने या हटाने का अधिकार देती है।

- Three RRBs newly included in the Second Schedule:

- Bihar Gramin Bank

- Jammu and Kashmir Grameen Bank
- West Bengal Gramin Bank

- Seven erstwhile RRBs excluded due to mergers, including Dakshin Bihar Gramin Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Uttar Bihar Gramin Bank, J & K Grameen Bank, Ellaquai Dehati Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank.
- Additionally, The Assam Co-operative Apex Bank Ltd has been added to the Second Schedule, making it a Scheduled Bank.
- इसके अतिरिक्त, असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) revised India's GDP growth forecast for the ongoing financial year to what percentage in its first monetary policy review of 2026?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2026 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर कितना किया?

- A) 7.0%
- B) 7.2%
- C) 7.3%
- D) 7.4%
- E) 7.6%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- On February 6, the Reserve Bank of India (RBI) revised the GDP growth forecast for the ongoing financial year to 7.4%, up from the earlier estimate of 7.3%.
- 6 फरवरी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- For FY27, real GDP growth for Q1 has been revised to 6.9% from 6.7%.

- FY27 की पहली तिमाही (Q1) के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दी गई है।
- Real GDP growth for Q2 FY27 has been revised to 7.0% from 6.8%, with risks considered evenly balanced.
- FY27 की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.8% से बढ़ाकर 7.0% कर दी गई है, और जोखिम संतुलित माने गए हैं।
- On the supply side, real Gross Value Added (GVA) growth is estimated at 7.3% in FY26.
- आपूर्ति पक्ष पर, FY26 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दर 7.3% अनुमानित की गई है।
- The GVA growth is driven by strong performance in the services sector and a revival in manufacturing.
- GVA वृद्धि में सेवाक्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार का प्रमुख योगदान है।

Ques: As announced by RBI Governor Sanjay Malhotra, what is the maximum compensation a customer can receive for losses due to small-value digital frauds?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित अनुसार, छोटे मूल्य के डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में ग्राहक को अधिकतम कितनी मुआवजा राशि मिल सकती है?

- A) ₹10,000
- B) ₹15,000
- C) ₹20,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI Governor Sanjay Malhotra announced measures to provide protection and compensation to customers against digital frauds.

- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों को सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करने के उपायों की घोषणा की।
- The announcement was made after the Monetary Policy Committee (MPC) meeting held on 6 February.
- यह घोषणा 6 फरवरी को आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद की गई।
- Customers affected by small-value digital frauds will receive 85% of the fraud amount, subject to a maximum limit of ₹25,000.
- छोटे मूल्य की डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को धोखाधड़ी की राशि का 85% मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 होगी।
- For example, if a person loses ₹50,000 in a digital fraud, 85% equals ₹42,500, but since the cap is ₹25,000, the compensation will be ₹25,000.
- उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को ₹50,000 का नुकसान होता है, तो उसका 85% ₹42,500 होता है, लेकिन अधिकतम सीमा ₹25,000 होने के कारण उसे ₹25,000 ही मिलेगा।
- If a person loses ₹20,000, then 85% equals ₹17,000, which is below the cap; hence the person will receive ₹17,000.
- यदि किसी व्यक्ति को ₹20,000 का नुकसान होता है, तो उसका 85% ₹17,000 होगा, जो सीमा से कम है, इसलिए उसे ₹17,000 मिलेगा।

Ques: SBI recently became India's which most valuable company by market capitalisation?

हाल ही में SBI बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की कौन-सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी?

- A) 2nd
- B) 3rd
- C) 4th
- D) 5th
- E) 6th

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) became India's fourth most valuable company by market capitalisation.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।
- SBI's market capitalisation surged to ₹10.9 lakh crore, allowing it to surpass Tata Consultancy Services (TCS).
- SBI का बाजार पूंजीकरण बढ़कर ₹10.9 लाख करोड़ हो गया, जिससे उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को पीछे छोड़ दिया।
- With this surge, SBI overtook TCS to claim the fourth position among India's top listed firms.
- इस वृद्धि के साथ SBI ने TCS को पीछे छोड़ते हुए भारत की शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों में चौथा स्थान हासिल किया।
- The three most valuable companies in India at present are Reliance Industries, HDFC Bank, and Bharti Airtel.
- वर्तमान में भारत की तीन सबसे मूल्यवान कंपनियाँ हैं — रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और भारती एयरटेल

Ques: Which company received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to participate in Centralized Payment Systems (CPS)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सेंट्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में भागीदारी के लिए किस कंपनी को सैद्धांतिक (In-principle) मंजूरी मिली?

- A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- B) Transcorp International Limited / ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड
- C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- D) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक
- E) Tata Payments Services / टाटा पेमेंट्स सर्विसेज

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Transcorp International Limited received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to participate in Centralized Payment Systems (CPS).
 - ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को सेंद्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में भाग लेने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।
 - With this authorization, Transcorp will be able to hold and operate a bank account directly with the RBI.
 - इस अनुमति के बाद ट्रांसकॉर्प RBI के साथ प्रत्यक्ष रूप से बैंक खाता संचालित कर सकेगा।
 - The company will also be allotted its own Indian Financial System Code (IFSC).
 - कंपनी को अपना स्वयं का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) भी आवंटित किया जाएगा।
 - Participation in CPS significantly strengthens Transcorp's banking services infrastructure and integration with India's payment ecosystem.
 - CPS में भागीदारी ट्रांसकॉर्प की बैंकिंग सेवा संरचना और भारत की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण को मजबूत बनाती है।
-

Ques: Which financial institution extended a USD 1 billion loan to the State Bank of India (SBI)?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस वित्तीय संस्था ने दिया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- C) Japan International Cooperation Agency (JICA) / जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी

- D) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
E) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) has extended a USD 1 billion (₹7,100 crore) loan to the State Bank of India (SBI).
 - जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1 बिलियन डॉलर (₹7,100 करोड़) का ऋण प्रदान किया।
 - The loan has a five-year maturity period.
 - इस ऋण की परिपक्वता अवधि (Tenure) पाँच वर्ष की है।
 - It includes a green shoe option of an additional USD 500 million.
 - इसमें अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है।
 - The interest rate is set at 90 basis points above the three-month SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
 - ब्याज दर तीन-महीने के SOFR (Secured Overnight Financing Rate) से 90 बेसिस पॉइंट अधिक तय की गई है।
-

Ques: RBI has proposed to increase the aggregate unsecured exposure limit of Urban Cooperative Banks (UCBs) to what percentage of total assets?

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की कुल असुरक्षित ऋण सीमा को कुल परिसंपत्तियों के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है?

- A) 12%
- B) 15%
- C) 18%
- D) 20%
- E) 25%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has proposed to enhance individual and aggregate unsecured loan limits for Urban Cooperative Banks (UCBs).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए असुरक्षित ऋण सीमाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- The aggregate unsecured exposure ceiling may be doubled from 10% to 20% of total assets.
- कुल असुरक्षित ऋण एक्सपोज़र सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% (कुल परिसंपत्तियों का) किया जा सकता है।

- **Individual unsecured loan limits (within the overall ceiling):**
 - Tier 1: ₹5 lakh
 - Tier 2: ₹7.5 lakh
 - Tier 3 & 4: ₹10 lakh

- **व्यक्तिगत असुरक्षित ऋण सीमा (कुल सीमा के भीतर):**
 - टियर 1: ₹5 लाख
 - टियर 2: ₹7.5 लाख
 - टियर 3 व 4: ₹10 लाख

- For housing loans (Tier 1 & 2 UCBs), **the** maximum tenor is proposed at 20 years, including moratorium.
- टियर 1 व 2 UCBs के लिए हाउसिंग लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष (मोराटोरियम सहित) प्रस्तावित है।
- The moratorium for Tier 1 & 2 housing loans **is** capped at 18 months from the first disbursement.
- टियर 1 व 2 के हाउसिंग लोन में मोराटोरियम अधिकतम 18 माह होगा।
- For Tier 3 & 4 UCBs, regulatory restrictions on loan tenor and moratorium are proposed to be removed, subject to Board-approved policies.
- टियर 3 व 4 UCBs को बोर्ड-स्वीकृत नीति के अनुसार लोन अवधि व मोराटोरियम तय करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- Individual housing loan exposure limits have been revised, going up to ₹3

crore for Tier 4 UCBs.

- व्यक्तिगत हाउसिंग लोन एक्सपोजर सीमा संशोधित कर टियर 4 UCBs के लिए ₹3 करोड़ तक की गई है।
- The loan limit for nominal members to purchase consumer durables is proposed to increase to ₹2.5 lakh per borrower.
- नाममात्र सदस्यों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद हेतु ऋण सीमा ₹2.5 लाख प्रति उधारकर्ता तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank Limited (CUB)?

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (CUB) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Dr. N. Kamakodi / डॉ. एन. कामकोडी
- B) R. Vijay Anandh / आर. विजय आनंद
- C) S. Ramesh Kumar / एस. रमेश कुमार
- D) R. Subramanian / आर. सुब्रमण्यम
- E) P. Mahesh / पी. महेश

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- R. Vijay Anandh has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank Limited (CUB).
- आर. विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (CUB) का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be three years.
- उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- He has replaced Dr. N. Kamakodi in this role.
- उन्होंने इस पद पर डॉ. एन. कामकोडी का स्थान लिया है।

About City Union Bank Limited :

- Established : 1904
 - HQ : Kumbakonam, Tamil Nadu
 - Tagline : Trust and Excellence since 1904
-

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) of Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)?

इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) P. R. Jaishankar / पी. आर. जयशंकर
- B) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- C) Rohit Rishi / रोहित ऋषि
- D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
- E) Ashwani Kumar / अश्विनी कुमार

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Rohit Rishi has been appointed as the Managing Director (MD) of Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).
- रोहित ऋषि को इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be three years.
- उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- Prior to this appointment, he served as Executive Director at Bank of Maharashtra.
- इस नियुक्ति से पहले वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक (Executive

Director) के पद पर कार्यरत थे।

- He has replaced P. R. Jaishankar as MD of IIFCL.
- उन्होंने IIFCL के MD पद पर पी. आर. जयशंकर का स्थान लिया है।

Ques: The Indian Army has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with which bank to provide specialised banking services and enhanced insurance benefits to Army personnel?

भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएँ और उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Indian Army and IDFC FIRST Bank have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to provide specialised banking services and enhanced insurance benefits to serving and retired Army personnel.
- भारतीय सेना और IDFC फर्स्ट बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएँ और बेहतर बीमा लाभ देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The MoU has been signed for a period of three years, valid till February 2029.
- यह MoU तीन वर्षों के लिए है और फरवरी 2029 तक मान्य रहेगा।
- Under the agreement, Personal Accidental Insurance cover of ₹60 lakh is provided without mandatory salary or pension credit.
- इस समझौते के तहत ₹60 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बिना वेतन या पेंशन

खाते में अनिवार्य जमा के उपलब्ध होगा।

- The insurance benefits are linked to minimum monthly credits instead.
- बीमा लाभों को न्यूनतम मासिक क्रेडिट से जोड़ा गया है।
- Additional benefits include ₹35 lakh nominee cover, ₹1 crore Air Accident Insurance, ₹4 lakh Higher Education Cover, and up to ₹2 lakh Girl Child Marriage Cover.
- अतिरिक्त लाभों में ₹35 लाख का नामिनी कवर, ₹1 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा, ₹4 लाख उच्च शिक्षा कवर, और ₹2 लाख तक कन्या विवाह कवर शामिल हैं।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First